www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 331 | जौनपुर, बुधवार, 22 जुलाई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पुलिसकर्मी शहीदय हमलावरों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन

अनंतनाग , (एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकियों ने पुलिस दल को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। इस हमले में जम्मू–कश्मीर पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल शहीद हो गए। घटना के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हमला अनंतनाग जिले के कोकेरनाग क्षेत्र के लाल चौक के पास उस समय हुआ जब पुलिस की टीम नियमित ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान संदिग्ध आतंकवादियों ने अचानक पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमले में हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए।अधिकारियों के मुताबिक, घटना बुधवार दोपहर करीब 12रू30 बजे हुई। घायल पुलिसकर्मी को तत्काल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (ळडब) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हरसंभव प्रयास किया। हालांकि गंभीर चोटों के कारण उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिसकर्मी की शहादत के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गई हैं और पूरे इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है।आतंकी हमले के तुरंत बाद जम्मू–कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान शुरू किया।

दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार ने फिर भेजा बातचीत का प्रस्ताव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जारी प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन के 33वें दिन बुधवार को हजारों समर्थक जंतर–मंतर पर जुटे, जिसके चलते एहतियातन दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसी बीच केंद्र सरकार ने दूसरी बार प्रदर्शनकारियों से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। सीजेपी की ओर से कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर पार्टी की कोर कमेटी चर्चा करने के बाद अंतिम निर्णय लेगी।सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बातचीत के प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए कहा कि संगठन सकारात्मक तरीके से सभी पहलुओं पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला सामूहिक सहमति के बाद ही लिया जाएगा।दिल्ली में कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (ब्च्थ्) की 20 अतिरिक्त कंपनियों को राजधानी भेजने का निर्णय लिया है। प्रत्येक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं, यानी करीब 2,000 सुरक्षाकर्मियों को कोलकाता से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जा रहा है।

यूपी में नहीं होगा किसी विदेशी आक्रांता का स्मारक : मुख्यमंत्री योगी

बौंडी, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बहराइच की धरती से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश में किसी विदेशी आक्रांता का स्मारक या उसके नाम पर मेला स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के शौर्य को भुलाकर पूर्ववर्ती सरकारों ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी का महिमामंडन किया, जबकि उनकी सरकार ने इस पर रोक लगाकर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान दिलाया। महसी के तेजवापुर स्थित बेड़नापुर रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने 352 करोड़ रुपये से अधिक की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कभी देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला बहराइच अब आकांक्षी नहीं, प्रेरणादायी जिला बन चुका है। नीति आयोग की रैंकिंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बहराइच बुनियादी ढांचे में प्रथम, कृषि में दूसरे और शिक्षा में चौथे स्थान पर पहुंचा है, जिसके लिए नीति आयोग ने जिले को 21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी है। मुख्यमंत्री ने बहराइच के लिए 7,000 करोड़ रुपये की बाराबंकी–बहराइच एक्सेस कंट्रोल्ड फोरलेन कॉरिडोर परियोजना, सरयू नदी पर 115 करोड़ रुपये की 22 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं, रुपईडीहा में इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर, बहराइच–खलीलाबाद रेल लाइन और गोरखपुर–शामली इकॉनमिक कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे जिले में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया, भ्रष्टाचार और उपद्रव का माहौल था, जबकि आज कानून का राज है। उन्होंने कहा कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए जेल या जहन्नुम ही स्थान है। वन्यजीव हमलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासन और वन विभाग को गश्त बढ़ाने, संवेदनशील गांवों में रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया सुभाषित, लिखा– निरूस्वार्थ कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ है

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आज बुधवार को सुभाषित शेयर किया है। पीएम मोदी ने 'एक्स' पोस्ट में संस्कृत श्लोक, "परकार्येषु युक्तात्मा स्वकार्ये क्षिप्रसाधनम्। सुहृत्कार्येषु निर्वृत्ती राजकार्येषु विक्रमः।।" भी साझा किया है, जिसका हिंदी अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों के कार्यों में पूरी निष्ठा से लगा रहता है, अपने व्यक्तिगत कार्यों को शीघ्रता एवं कुशलता से पूरा करता है, मित्रों के कार्यों को निरूस्वार्थ भाव से संपन्न करता है और राष्ट्र के कर्तव्यों में अपना पूर्ण पराक्रम व शौर्य प्रदर्शित करता है, वही श्रेष्ठ है।" प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बीते दिन मंगलवार को भी सुभाषित शेयर किया गया था। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि एकाग्रता और संकल्प हमारे स्नायुतंत्र की भांति है, जिन्हें नियमित अभ्यास और सही दिशा में प्रयत्न के माध्यम से निरंतर विकसित और सशक्त बनाया जा सकता है। समय के साथ ये दोनों और अधिक दृढ़ तथा प्रभावशाली बनते जाते हैं।" इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने सुभाषित पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, "आज हमारे युवा साथी धैर्य, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से ऐतिहासिक सफलता हासिल कर रहे हैं। यही विकसित हो रहे भारत की सबसे बड़ी ताकत है।" , जिसका हिंदी अर्थ है कि जो मनुष्य संकट के समय कभी विचलित नहीं होता, बल्कि धैर्य, कुशलता और सावधानी के साथ उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है तथा समय आने पर दुखों को भी सहजता से सहन करता है, वह अंततरू कभी पराजित नहीं होता, बल्कि विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त करता है।

जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुका से की मुलाकात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जारी विरोध–प्रदर्शनों के बीच बड़ा राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचकर जलवायु कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का हाल–चाल जाना। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कथित नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर–मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध–प्रदर्शन 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यह घटनाक्रम भाजपा के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद हुआ है कि उनकी तरफ से सरकार के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। सोमवार देर रात जंतर–मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दिपके ने कहा कि जो कोई भी प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करना चाहता है, उसे विरोध स्थल पर आना होगा। 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने वाले वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मंगलवार शाम सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से तुरंत स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच शाम करीब 7.30 बजे एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल लाया गया।

छात्रों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा, संसद में करें चर्चा – राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र के दौरान युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के छात्रों और युवाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हथियार के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने इसे छात्रों को भटकाने का एक असफल प्रयास करार दिया। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि भारत का समझदार युवा इन सभी कोशिशों को अच्छी तरह समझता है और वह विकास तथा राष्ट्र निर्माण का रास्ता ही चुनेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार युवाओं के प्रति संवेदनशील है और यह सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ, खासकर छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ नेता जनता के बीच बनावटी गुस्सा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद विपक्ष संसद के बजाय सड़कों पर समाधान ढूंढने का अनुचित प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में गंभीर है, तो उसे सत्र में हंगामा करने के बजाय सदन के भीतर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। संसद में मचे हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि लोकसभा की कार्यवाही 23 जुलाई सुबह 11रू00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

दिल्ली में छात्रों के आंदोलन में गुंडे घुसे थेय विपक्षी दलों पर साधा निशाना - केशव प्रसाद

बरेली, (संवाददाता)। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर छात्रों को ढाल बनाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। मौर्य ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के सवाल पर कहा कि छात्रों के आंदोलन में गुंडे घुस गए थे। कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। बुधवार को बरेली पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेसवार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी पर शिक्षा के मामले में बोलने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने कल्याण सिंह सरकार द्वारा लागू नकल अध्यादेश वापस ले लिया था। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीट पेपर में सेंध लगाने की कोशिश हुई थी, जिस पर कड़ी कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि नीट दोबारा सफलतापूर्वक आयोजित की गई और छात्र इससे संतुष्ट हैं। हालांकि, विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर मौर्य ने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी के कहने मात्र से इस्तीफा नहीं होता है। उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश भाजपा 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सपा को विकास देखा नहीं जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन का स्वागत करती है। लेकिन आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने या पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के गुंडे आंदोलन में घुस गए। इन दलों ने छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी हैं। मौर्य ने कहा कि देश का युवा इसका जवाब आगामी चुनाव में देगा। केशव प्रसाद मौर्य ने दोहराया कि सरकार मासूमों पर लाठीचार्ज नहीं करती है।

जरूरत पड़ी तो सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जाऊंगी – ममता बनर्जी

कोलकाता, (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने दिल्ली में सीजेपी के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगी। मंगलवार को कोलकाता में टीएमसी की वार्षिक 21 जुलाई शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नीत केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाया। ममता ने मंगलवार को दिल्ली में हुई झड़पों का जिक्र करते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली जाऊंगी और सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होऊंगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारी जब संसद परिसर के करीब पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार घुमा ली और वहां से चले गए। हालांकि, ममता ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई कर लोकतंत्र के प्रति असहिष्णुता दिखाई है। ममता ने आरोप लगाया कि सवाल पूछने वाले छात्रों को संवाद के बजाय लाठी और आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तानाशाही की हदें पार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है।

रामधन गबन और लूट विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की चल रही अहम बैठक

अयोध्या।रामधन गबन और लूट विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक चल रही है।अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में नए महासचिव की नियुक्ति, तीन खाली ट्रस्टी पदों को भरने, सीईओ चयन प्रक्रिया, दान की गिनती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने सहित एस आईटी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है।अंतिम फैसलों का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है

सरकार के साथ कोई डील तो नहीं हो गई - अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। लोकसभा में बुधवार को नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मामले पर तुरंत चर्चा कराने की मांग रखी। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हो गए। उन्होंने स्पीकर पर खुद को बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपने इनको और उनको बोलने का मौका दे दिया, पर हमारा क्या। आपने समझौता कर लिया क्या? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह विषय किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के छात्रों और नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर छात्रों की आवाज नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर उन्होंने कहा– इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे, तब मंत्री से ले लेंगे। अगर मंत्री सदन में इस्तीफा नहीं देंगे तो सदन के बाहर इस्तीफा ले लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नेताओं के हाथ तोड़े गए, सिर फोड़े गए और कपड़े फाड़े गए। अखिलेश यादव ने बताया कि वह और राहुल गांधी मजबूरी में प्रधानमंत्री आवास गए थे। अगर संसद के भीतर उनकी बात सुन ली जाती, तो उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री संसद के बाहर तो बोल सकते हैं, लेकिन देश के युवाओं के लिए सदन के भीतर आकर क्यों नहीं बोल रहे। अखिलेश से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में बोलते हुए कहा, संसद में कोई भी चर्चा तय नियमों और व्यवस्था के तहत ही होती है। रिजिजू ने स्पीकर से अनुरोध किया कि सभी दलों के फ्लोर नेताओं के साथ बातचीत करके चर्चा का नियम, समय और दिन तय किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार नीट और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद स्पीकर ने सदन में मौजूद सदस्यों से पूछा कि क्या सभी लोगों की बातें मुझ तक पहुंच गई हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं और ये भी चर्चा जाते हैं। सरकार चर्चा करने को तैयार है।

संपादकीय

गंभीर कमियां उजागर

संक्षेप देखकर ठहर जाएं, तो मालूम होगा कि श्रम बल में भागीदारी बढ़ी है और बेरोजगारी दर घटी है। लेकिन बारीकी में जाएं, तो सकारात्मक कथानक में मौजूद कई गंभीर कमियां उजागर होने लगती हैं। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रोजगार की स्थिति पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) की ताजा रिपोर्ट चमकती हेडलाइन के लिए मसाला तो देती है, लेकिन उसके अंदर उतरते ही कड़वी हकीकतों से सामना होने लगता है। सिर्फ सार–संक्षेप देखकर ठहर जाएं, तो मालूम होगा कि श्रम बल में महिलाओं सहित कामकाजी उम्र के सभी व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ी है और बेरोजगारी दर घटी है। लेकिन बारीकी में जाएं, तो सकारात्मक कथानक में मौजूद कई गंभीर कमियां जाहिर होने लगती हैं। मसलन, यह उत्साह से बताया गया है कि बड़े शहरों में 55 फीसदी से अधिक श्रमिक अब नियमित वेतनभोगी हैं। मगर रिपोर्ट में यह तथ्य भी मौजूद है कि इनमें बहुत बड़ा हिस्सा वैसी नियमित नौकरियों का है, जिनमें पीएफ, पेंशन, सवैतनिक अवकाश, या स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षाएं नहीं मिलतीं। गिग कर्मियों की बढ़ती संख्या को रोजगार वृद्धि बताया गया है, जबकि ऐसे कर्मियों को किसी तरह के श्रम अधिकार या जॉब सिक्योरिटी हासिल नहीं हैं। महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ कर 27.2 फीसदी होने का दावा भी विवादास्पद है, क्योंकि खुद रिपोर्ट मानती है कि कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा आज भी कम या शून्य वेतन वाले घरेलू कार्यों या असंगठित मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी कम वेतन मिलता है, यह स्वीकार किया गया है। बेरोजगारी दर गिर कर 4.9 प्रतिशत रह जाने की बात कही गई है, लेकिन अर्ध–रोजगार या योग्यता से कम दर्जे का काम मिलने के व्यापक चलन पर रिपोर्ट चुप है। दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत यह है कि लाखों पोस्ट–ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग डिग्री धारक युवा फिलहाल महानगरों में क्लर्क, डिलीवरी बॉय या डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी करने को मजबूर हैं। फिर याद रखना चाहिए कि ये रिपोर्ट मिलियन–प्लस शहरों के बारे में है। छोटे शहरों और ग्रामीण भारत की कहानी इसमें शामिल नहीं है, जहां महानगरों की तुलना में काफी कम कमाई होती है। तो एक बार फिर वही कहानी है। रोजगार के मोर्चे पर नीतिगत विफलता को छिपाने के लिए एक रिपोर्ट को इस इस तरह लिखा गया है, जिससे लोग श्फील–गुड्य महसूस करें।

भारत–यूनाइटेड किंगडम सीईटीए लागू हुआ

भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य बाजार की बेहतर पहुँच, सरल व्यापार प्रक्रियाओं, सेवा क्षेत्र में व्यापक प्रतिबद्धताओं तथा पेशेवरों की अधिक सुगम आवाजाही के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। सीईटीए व्यापार संबंधी बाधाओं को कम करके और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर कृषि, मत्स्य, विनिर्माण, सेवा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर सृजित करता है। साथ ही, यह संतुलित बाजार पहुँच और चरणबद्ध शुल्क उदारीकरण के माध्यम से भारत के संवेदनशील क्षेत्रों के हितों का संरक्षण भी सुनिश्चित करता है। यह समझौता डिजिटल व्यापार, नवाचार, सतत् विकास तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाने को बढ़ावा देता है। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाते हुए यह समझौता अधिक समावेशी और भविष्य उन्मुख आर्थिक साझेदारी की मजबूत आधारशिला रखता है। भारत–यूनाइटेड किंगडम सीईटीए रू एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता भारत–यूनाइटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) एक आधुनिक, व्यापक तथा ऐतिहासिक व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य बेहतर बाजार पहुँच, व्यापार उदारीकरण तथा शुल्क में रियायतों के माध्यम से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक एकीकरण को और अधिक सुदृढ़ करना है। इस समझौते के तहत भारत को मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम द्वारा अब तक की सबसे महत्त्वाकांक्षी सेवा प्रतिबद्धताओं में से एक का लाभ मिलेगा। भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को, जो व्यापार मूल्य के लगभग 100 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, शून्य–शुल्क पहुँच प्रदान किए जाने से सीईटीए के जरिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ होने की अपेक्षा है। इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार, निवेश में वृद्धि तथा व्यवसायों के लिए नए अवसर सृजित होने की भी संभावना है। अपने आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व से परे सीईटीए को एक समावेशी तथा भविष्य उन्मुख समझौते के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचें। यह केवल एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक सुदृढ़, नवाचार–आधारित और जन–केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला भी रखता है। भारत–यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय व्यापार भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक मजबूत और विस्?तृत होती आर्थिक साझेदारी है। वर्ष 2025 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.96 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था 3.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की रही। यह वैश्विक व्यापार में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के महत्व को दर्शाता है। वर्ष 2025–26 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार 25.12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा। इस अवधि में यूनाइटेड किंगडम को भारत का निर्यात 13.44 अरब अमेरिकी डॉलर तथा आयात 11.68 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसके परिणामस्वरूप भारत को 1.76 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ। सेवाओं का व्यापार भी समान रूप से सशक्त रहा है। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय सेवा व्यापार 35.44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा। इस अवधि में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को 21.66 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की सेवाओं का निर्यात किया तथा 13.78 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की सेवाओं का आयात किया, जिससे भारत को सेवा व्यापार में 7.88 अरब अमेरिकी डॉलर का अधिशेष प्राप्त हुआ। सीईटीए से प्रमुख हितधारकों को होने वाले लाभ सीईटीए को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। साथ ही, यह समझौता ये भी सुनिश्चित करता है कि व्यापार से होने वाले लाभ व्यापक रूप से समाज के सभी वर्गों तक पहुँचें। शुल्क समाप्त कर दिए जाने से भारतीय किसानों तथा मत्स्यपालकों को यूनाइटेड किंगडम के बाजारों तक बेहतर पहुँच मिलने की उम्मीद है। इससे नए निर्यात अवसर सृजित होने तथा उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। यह समझौता वन पर निर्भर समुदायों की आजीविका के महत्व को स्वीकार करता है। साथ ही, यह प्राकृतिक संसाधनों के उत्तरदायी प्रबंधन तथा पर्यावरणीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्?पोनेंट्स, प्लास्टिक तथा कार्बनिक रसायन जैसे श्रम–प्रधान क्षेत्रों में निर्यात बढ़ने की संभावना है। इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह समझौता समावेशी तथा भविष्य के लिए तैयार विकास पर विशेष बल देता है। इससे महिलाओं, युवाओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), व्यवसायों तथा पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार होगा। इसमें महिलाओं तथा अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की व्यापार, नवाचार और उद्यमिता में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

संसद के मानसून सत्र में जारी रहेगी गरमा-गरमी

डॉ. ज्ञान

सीजेपीआंदोलन और वांगचुक को जबरदस्ती हटाने के साथ–साथ प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके मसला सुलझाने से बचने की केंद्र की कार्रवाई की विपक्ष और अन्य लोगों ने व्यापक निंदा की है। जहां संसद के मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर हंगामा होने की संभावना है, वहीं बाहर भी यह विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के संसद मार्च को विफल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आखिरकार लाठी चार्ज का सहारा लिया। विपक्षी नेताओं, सीजेपी कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लेखकों, कलाकारों, मशहूर हस्तियों और आम लोगों का कहना है कि यह लोकतांत्रिक आंदोलन को जबरदस्ती दबाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। सीजेपीआंदोलन, जो 16 मई को अभिजीत दिपके द्वारा एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया था, अब इतना बड़ा हो चुका है कि जानकारों का मानना है कि इसे दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसे समाज के सभी वर्गों और देश की सभी विपक्षी पार्टियों से भारी समर्थन मिला है। अब जाकर खबर आई है कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों से बात करने को तैयार है, पर अब तक वह सीजेपी के आन्दोलन का जवाब जोर जबरदस्ती से देती रही है। उन्होंने लगभग विरोध स्थल को सील कर दिया और प्रदर्शनकारियों के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दीं। अब सीजेपी कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है, विरोध जारी रखने का संकल्प लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की है। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के तेज होने के कारण मानसून सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। हालांकि, विपक्ष केंद्र सरकार द्वारा सीजेपीके श्लोकतांत्रिक विरोध को दबानेश और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (जिनके इस्तीफे की वे पहले ही मांग कर चुके हैं) को बचाने के मुद्दे पर सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। संसद के भीतर विपक्ष के विरोध का एक खास मौका तब आएगा जब केंद्र सरकार श्विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025श नाम का एक संशोधित बिल पेश करेगी, जिसे पहले श्हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (एचईसीआई) बिलश के नाम से जाना जाता था। यह बिल अपने पुराने रूप में काफी विवादास्पद था। नया शशिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025श मौजूदा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) की जगह एक ही उच्च शिक्षा नियामक लाने का प्रस्ताव करता है।विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए देश में उच्च शिक्षा को बर्बाद कर रही है और हिंदुत्व–ब्रांड की शिक्षा थोपने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इसके प्रावधान मौजूदा कानूनी ढांचे को नहीं बदलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष के साथ सीधा टकराव होगा, क्योंकि विपक्ष परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर पहले ही उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार–बार प्रधान पर राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी भ्रष्टाचार और सिस्टम की विफलता के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर पेपर लीक का हवाला देते हुए पूरे सिस्टम को श्धोखाधड़ीश करार दिया है और देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने प्रधान पर यह आरोप भी लगाया था कि वे सीबीएसई के उस फैसले में शामिल थे, जिसके तहत एक विवादित कंपनी को ऑन–स्क्रीन मार्किंग का ठेका दिया गया था।एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, श्केंद्र ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला, और इसका असर कई छात्रों के भविष्य पर पड़ा। जब दूसरी राजनीतिक पार्टियां उनके (वांगचुक के) समर्थन में आईं, तो सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी रही। कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) के नेताओं, जिनमें सुप्रिया सुले और कई अन्य शामिल हैं, ने वहां (जंतर–मंतर) जाकर एक जैसी मांग रखी।श्आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, श्प्रधानमंत्री ने सिर्फ सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। छात्रों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और इसके बजाय वह उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।श राजनीति टीएससीप्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, श्उन्होंने (वांगचुक ने) सिर्फ बातचीत की मांग की थी, फिर भी हफ्तों तक उनकी इस अपील पर कोई जवाब नहीं दिया गया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध पर बातचीत होनी चाहिए, न कि चुप्पी साधी जानी चाहिए। ...जनता का भरोसा पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान से हासिल होता है – न कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने या बातचीत से इनकार करने से।श शिवसेना (यूबीटी)नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में प्रदर्शन स्थल से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हटाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया देख रही है कि देश में जबरदस्ती लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है, जहां शांतिपूर्ण विरोध को भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष

मल्लिकार्जुन खडगे ने सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाए जाने की निंदा करते हुए इसे श्लोकतंत्र और संविधान पर एक काला धब्बाश बताया। खड़गे ने कहा, श्चाहे प्रो. जीडी अग्रवाल हों, जिन्होंने मां गंगा को बचाने के लिए 111 दिनों तक आमरण अनशन किया, या हरियाणा के ओलंपिक पहलवान, चाहे हमारे 750 किसान हों, दलित और आदिवासी हों, या पेपर लीक की भेंट चढ़े 25 बच्चे और उनके परिवार हों – इस जालिम सरकार ने किसी को नहीं बख्शा... उनकी नजर में, जो कोई भी आवाज उठाता है, वह श्राष्ट्र–विरोधीश या श्परजीवीश है!श समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, श्दमनकारी भाजपा सरकार की इस अनुचित कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की मानवीय और लोकतांत्रिक छवि को बुरी तरह धूमिल और खंडित किया है... भाजपा की सोच बांटने वाली हैय इसीलिए जहां भी एकता, सद्भाव और एकजुटता होती है, भाजपा डर के मारे प्रतिक्रियावादी रवैया अपनाती है और आंदोलनों को तितर–बितर कर देती है। लेकिन भाजपा भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी श्डिजिटल एकताश के जरिए वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम है। ऐसा हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा... ।श आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है, श्यह अहंकार गलत है। श्कॉकरोच आंदोलनश को कुचलने के बजाय, देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएं। सोनम वांगचुक के साथ जबरदस्ती करना मोदी सरकार की हार है।श्सीजेपीआंदोलन और वांगचुक को जबरदस्ती हटाने के साथ–साथ प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके मसला सुलझाने से बचने की केंद्र की कार्रवाई की विपक्ष और अन्य लोगों ने व्यापक निंदा की है।

भारत से टकराने की जिद बड़ी भारी पड़ती है, हिंदुस्तान के हिस्से का बिल भी भर रहा है पाकिस्तान

नीरज

भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। नई दिल्ली का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां 1960 जैसी नहीं रहीं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, ऊर्जा की आवश्यकता, नई

प्रौद्योगिकी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। ऐसे में संधि की समीक्षा और नए सिरे से विचार स्वाभाविक आवश्यकता है। सीमापार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुके पाकिस्तान की आज ऐसी दुर्गति हो चुकी है कि वह भारत के खिलाफ साजिश रचने की कीमत भी अपनी जेब से चुका रहा है। दरअसल, सिंधु जल संधि को लेकर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने की नाकाम कोशिश में इस्लामाबाद न केवल अपनी ओर से खर्च उठा रहा है, बल्कि भारत के हिस्से का व्यय भी खुद अदा कर रहा है। यानी जिस देश को वह कटघरे में खड़ा करना चाहता है, उसी का बिल भी उसे भरना पड़ रहा है। यह दृश्य पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली, कूटनीतिक बेबसी और बौखलाहट का सबसे बड़ा प्रमाण है। दुनिया के सामने भारत को घेरने निकला पाकिस्तान आज अपनी ही बनाई चाल में फंसकर उपहास का पात्र बन गया है। हम आपको बता दें कि सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत छह नदियों के जल के बंटवारे का ढांचा तय किया गया था। दशकों तक भारत ने संधि का पूरी निष्ठा से पालन किया, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को संरक्षण देता रहा। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ संदेश दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का विश्वसनीय और स्थायी रूप से परित्याग नहीं करता, तब तक सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी क्रम में भारत ने संधि से जुड़ी कार्यवाहियों में अपनी भागीदारी स्थगित कर दी। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। नई दिल्ली का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां 1960 जैसी नहीं रहीं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, ऊर्जा की आवश्यकता, नई प्रौद्योगिकी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। ऐसे में संधि की समीक्षा और नए सिरे से विचार स्वाभाविक आवश्यकता है। इसके विपरीत पाकिस्तान हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस मध्यस्थता प्रक्रिया से वह भारत पर दबाव बनाना चाहता है, उसी का पूरा आर्थिक बोझ भी उसे स्वयं उठाना पड़ रहा है। यह उस कूटनीतिक दिवालियेपन का प्रतीक है जिसमें पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी दलीलें जीवित रखने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार दिखाई देता है। सच्चाई यह भी है कि सिंधु जल संधि से दशकों तक सबसे बड़ा लाभ पाकिस्तान को मिला। भारत, ऊपरी प्रवाह वाला देश होने के बावजूद, संधि की कठोर शर्तों का पालन करता रहा। अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि यह व्यवस्था भारत के हितों के अनुरूप नहीं रही। इसके बावजूद भारत ने जिम्मेदार राष्ट्र का परिचय दिया। लेकिन जब पड़ोसी देश आतंकवादियों को शरण दे, प्रशिक्षण दे और भारत के निर्दोष नागरिकों का रक्त बहाने वालों को संरक्षण प्रदान करे, तब केवल सद्भावना के आधार पर संबंध नहीं चल सकते। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाने से वास्तविकता नहीं बदलती। आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और सहयोग, आतंकवाद और विश्वास, ये तीनों एक साथ नहीं चल सकते। यदि इस्लामाबाद यह सोचता है कि वह एक ओर आतंकियों को पालता रहेगा और दूसरी ओर जल समझौतों तथा वैश्विक संस्थाओं की आड़ लेकर भारत पर दबाव बनाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। भारत ने बार–बार संयम दिखाया है, लेकिन संयम को कमजोरी समझना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, जल हितों और संप्रभु अधिकारों से किसी प्रकार का समझौता करने वाला नहीं है। यदि पाकिस्तान वास्तव में क्षेत्र में शांति चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी धरती से संचालित सीमापार आतंकवाद की फैक्ट्रियों पर स्थायी ताला लगाना होगा। बहरहाल, पाकिस्तान के नीति–निर्माताओं के लिए यह घटनाक्रम स्पष्ट संदेश है। जो देश आज भारत का हिस्सा भी अपनी जेब से भरने को विवश है, उसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था, अपने शासन और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत को धमकियों या अंतरराष्ट्रीय मंचों की कार्यवाहियों से झुकाया नहीं जा सकता। भारत की ओर से संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि पाकिस्तान ने सीमापार आतंकवाद को हमेशा के लिए बंद नहीं किया, तो उसे केवल आर्थिक ही नहीं, कूटनीतिक, सामरिक और रणनीतिक स्तर पर भी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शांति का मार्ग आतंकवाद छोड़ने से होकर जाता है, न कि दुनिया भर में शिकायतों का पुलिंदा लेकर घूमने से। समय रहते पाकिस्तान को यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी, क्योंकि नया भारत अपनी सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।

अमेरिका ने दुनिया को अपने सपनों में गूंथा

हरिशंकर व्यास

अमेरिका ढाई सौ वर्ष का हुआ। इस शुक्रवार–शनिवार उसके जश्न की कुछ झलकियां टीवी पर देखी। एक परिचित धुन कानों में पड़ीकृ डोंट स्टॉप बिलीविन बरसों पुराना यह गीत मेरी पचास वर्षों की स्मृतियों को खोल गया। गीत सुन मुझे ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की आवाज भी याद हो आई। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने बॉर्न टू रन और बाद में बॉर्न इन द यू.एस.ए. को जिस अंदाज में गया, वह गजब ही था। अचानक समझ आया कि पिछले पचास वर्षों में मैंने अमेरिका को जितना समझा, पढ़ा, और उस पर जितना लिखा उससे कहीं अधिक तो उसके गीतों की जुबानी अमेरिका की यात्रा है। संयोग है मैं पचास साल से गवाह हूं। मैं जब छोटे से कस्बे भीलवाड़ा से निकलकर दिल्ली के जेएनयू में पहुँचा था, तब मेरे भीतर भी एक दौड़ शुरू हुई थी। दुनिया को जानने की, समझने की, पढ़ने की और अपनी टूटी–फूटी हिंदी में उसे लिखने की। वह आपातकाल का समय था। मेरे लिए जेएनयू की लाइब्रेरी कौतुकता के मेरे डीएनए की मानों पूर्ति थी। विदेशी पत्र–पत्रिकाएं, अखबार, विश्लेषणकृ जो हाथ लगा, पढ़ता था। उसी से संयोग बना और कुछ ही महिनों में मैंने वैश्विक घटनाओं पर लिखना शुरू किया। 16 दिसंबर 1976 को दैनिक हिंदुस्तान में पहला लेख छपा, वह भी अंतरराष्ट्रीय विषय पर। तब भारत में आपातकाल था। इसलिए हिंदी अखबारों को दुनिया पर लिखा चाहिए था और सुरक्षित भी था। इसलिए सोवियत संघ, अमेरिका, यूरोप और शीतयुद्ध की राजनीति मेरा शगल बनी। कुछ ही महीनों में दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं से लेकर राजेंद्र माथुर के नेतृत्व वाले नई दुनिया में परिक्रमा कॉलम लिखने का मेरा सिलसिला बना, पत्रकारिता की भूमिका बनी। उन दिनों चालीस, साठ और पचहत्तर रुपए प्रति लेख मिलते थे। आवश्यकता से अधिक। नतीजतन कनॉट प्लेस की सेंट्रल न्यूज एजेंसी से टाइम, द इकोनॉमिस्ट, हिम्मत, ओपिनियन, क्वेस्ट जैसी पत्रिकाएं खरीदता। बगल के प्रिया और चाणक्य सिनेमाघरों में हॉलीवुड फिल्में देखता। दुनिया को पढ़ने के साथ–साथ देखने की आदत भी बनी। वह अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड और सोवियत नेता ब्रेजनेव का समय था। अब ट्रंप और पुतिन का है। 1975–76 का अमेरिका आज भी मेरी स्मृति में बहुत साफ है। सैगॉन में अमेरिकी दूतावास की छत से हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने की तब तस्वीरें थीं। राष्ट्रपति निक्सन और वाटरगेट कांड की गूंज थी। 1976 में अमेरिका के दो सौ वर्ष पूरे हुए। उत्सव हुआ, मगर अमेरिका में युद्ध हारने की पीड़ा थी, गहरी निराशा थी। सत्ता पर अविश्वास था और भविष्य को लेकर अनिश्चितता। उसी दौरान ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का संभवतरू पहला बड़ा गीत बॉर्न टू रन सुपरहिट हुआ। वह तब एक पीढ़ी की बेचैनी की आवाज था, जो कह रही थीकृयहां दम घुट रहा है, कहीं निकल चलो। छोटे शहर से बाहर निकलो। सीमाएं तोड़ो। अपना भविष्य खुद बनाओ। स्प्रिंगस्टीन अमेरिकी मजदूर, छोटे शहरों और अमेरिकी सपने की प्रामाणिक आवाज बन गए। वह आवाज, जो रोनाल्ड रीगन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को ठेंगा दिखाती रही है। क्योंकि उनकी आवाज में अमेरिकी सत्ता नहीं, बल्कि व्यक्ति और नागरिक के सपनों का अमेरिका है। वह अमेरिका, जहां व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रतिभा से अपना भविष्य गढ़ता है। खुद अवसर खोजता है, मेहनत से अपने सपनों को साकार बनाता है। फिर 1981 में एक गीत आया –डोंट स्टॉप बिलीविन। जर्नी बैंड के गायक स्टीव पेरी की आवाज के इस गीत ने 1981 अमेरिका को ऐसा बांधा कि आज भी वह सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसकी शुरुआती पंक्तियांकृएक छोटे कस्बे की लड़कीज् और एक छोटे कस्बे का लड़काज्कृ सीधे अमेरिकी मानस को छू गई। साधारण परिवार, छोटे शहर पर बड़े सपने। गीत का संदेश जो टूक यह कि कृ उम्मीद मत छोड़ो। विश्वास बनाए रखो। मतलब अमेरिका सपनों के लिए, विश्वास के साथ है। तब से अब तक आर्थिक मंदी हो, व्यक्तिगत संकट हो, खेल का मैदान हो या राष्ट्रीय उत्सवकृअमेरिका में गीत हर जगह गाया जाता है। ढाई सौवें स्थापना दिवस के समारोह में जब हजारों अमेरिकी इसके अंतिम कोरस तक एक साथ पहुंचे, तो सचमुच लगा कि वे गीत नहीं मात्र नहीं गा रहे थे वे निज विश्वास में देश को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अचानक मन में प्रश्न उठा। क्या दुनिया के किसी और देश में ऐसे गीत है, जिसे पूरा समाज अपने साझा सपने की तरह गाता हो? रूस, चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान या भारतकृहर देश के पास अपने राष्ट्रगान है, देशभक्ति के गीत हैं, युद्ध के गीत हैं, क्रांति के गीत हैं। लेकिन क्या ऐसे गीत है, जो साधारण नागरिक से इतना भर कहेकृसपने देखो, हार मत मानो, आगे बढ़ो, विश्वास रखों? यही अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। अधिकांश देशों ने अपने नागरिकों को इतिहास, धर्म, राजसत्ता, जातीय गौरव या राष्ट्रीय अस्मिता के आधार पर जोड़ा या बनाया। मगर अमेरिका ने वेयक्कित, निज सपनों से देश गढ़ा। अमेरिका में जो रहा है, जो हुआ या होगा, उसमें निज मनुष्य के सपनों की पहली भूमिका है फिर संविधान, प्रशासन, राष्ट्रपति की है। डोनाल्ड ट्रंप हों या इलॉन मस्क, कमला हैरिस हों या सुंदर पिचाईकृसबकी कहानियों का आरंभ एक ही जगह से होता हैकृ वह स्वतंत्र मनुष्य के सपने से है। इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका को समझना हो तो उसके राष्ट्रपतियों से पहले उसके गीतों को सुने। साफ जाहिर होगा कि वे अमेरिका कैसे सोचता है, कैसे टूटता है, कैसे संभलता है और क्यों हर संकट के बाद भी अपने भविष्य पर विश्वास बनाए रखता है। अमेरिका का राष्ट्रगान द स्टार स्पैंगल्ड बैनर है। इसे 1814 में फ्रांसिस स्कॉट की ने बाल्टीमोर के युद्ध के दौरान लिखा था। इसकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति हैकृओयअर द लैंड ऑफ द फ्री एंड द होम ऑफ द ब्रेवकृयानी स्वतंत्र लोगों की भूमि और वीरों का घर। यह गीत युद्ध के बीच झंडे के बच जाने का गीत है। गणराज्य की रक्षा का गीत है। लेकिन अमेरिका और अमेरिकियों का सपना राष्ट्रगान में नहीं बसता। वह लोकप्रिय गीतों में सांस लेता है। यदि राष्ट्रगान बताता है कि अमेरिका कैसे बचा, तो उसके गीत बताते हैं कि अमेरिका किस विश्वास पर खड़ा हुआ था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसलिए अमेरिका भूगोल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। वह अपने नागरिकों से पहले यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, किस धर्म, किस जाति या किस वंश से आए हो। वह उनके सपने देखता है, सपनों को मौका देता है। इसलिए दुनिया भर के लोग ढाई सौ वर्षों से अपने सपने लेकर मुख्यतरू अमेरिका की ओर ही भागे हैं। बिरले ही मनुष्य होंगे जो सपने लेकर चीन, रूस, भारत या किसी और देश में जाएं। लोगों के लिए अमेरिका कमाई से पहले सपनों को साकार बनाने का मुकाम है। दुनिया के बाकी देश अपने को मदरलैंड, फादरलैंड या धर्मराष्ट्र कहते हैं, मगर अमेरिका अकेला ऐसा देश है, जहां सपना पहले है, बाकी सब बाद में। पहले सपना, फिर पूंजीवाद। कोलंबस जब समुद्र में निकला था, तब उसके पास कोई निश्चित नक्शा नहीं था। उसके पास केवल विश्वास था कि क्षितिज के पार कुछ नया मिलेगा। उसी खोज की मानसिकता ने बाद में पूरे अमेरिकी महाद्वीप का चरित्र गढ़ा। अमेरिका का जन्म किसी नस्ल विशेष, भाषा या धर्म से नहीं हुआ। उसका जन्म एक संभावना से हुआ जिसका संबल विश्वास था। तभी अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात हथियार से ज्यादा पूरी पृथ्वी को सपनों की और दौड़ाने वाला देश है। अमेरिकी संविधान का मूल भाव है कि यदि तुममें प्रतिभा है, जोखिम उठाने का साहस है और मेहनत करने की इच्छा है, तो भविष्य तुम्हारा हो सकता है। यही उसका मूल सूत्र और सांस्कृतिक ताकत है। अमेरिका में राष्ट्रपति, सरकारें बदलती रहती हैं। नीतियां बदलती रहती हैं। कभी उदारवाद, कभी अनुदारवाद, कभी राष्ट्रवाद। कभी निक्सन और रीगन हैं, तो कभी ओबामा, कभी ट्रंप। लेकिन इन सबके बीच एक चीज लगातार है और वह यह विश्वास है कि हम कर सकते हैं, फिर महान बन सकते हैं।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र यूपी में ओबीसी वर्ग पर अत्याचार रोकने की मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा लोगों के खिलाफ कथित अत्याचारों और हत्याओं पर अंकुश लगाने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौपा है। जिलाध्यक्ष संजय माली ने आरोप लगाया कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामंतवाद के बढ़ते संरक्षण के कारण ओबीसी वर्ग के साथ अत्याचार, संवैधानिक अधिकारों का हनन, फर्जी मुठभेड़, थानों में हिरासत में मौतें और हत्याएं बढ़ गई हैं। जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी वर्ग को गुमराह किया गया है और शासन–प्रशासन के दोहरे रवैये से यह वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है, जहां ओबीसी की हर जाति के साथ अन्याय और हत्याएं न हुई हों। जिला कांग्रेस कमेटी–पिछड़ा वर्ग विभाग, जौनपुर ने राष्ट्रपति से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ हो रहे घोर अन्याय, शोषण और हत्याओं को रोकने के लिए शासन–प्रशासन को संज्ञान लेने का निर्देश दिया जाए और ओबीसी वर्ग का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

नौपेड़वां CHC अधीक्षक पर गिरी गाज, बायोमेडिकल कचरा निस्तारण में लापरवाही और अव्यवस्था पर हुआ तबादला

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) नौपेड़वां में अव्यवस्था और बायोमेडिकल कचरे के असुरक्षित निस्तारण के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अस्पताल की खामियों का वीडियो वायरल होने के बाद अधीक्षक डॉ. गोपेश कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जन आक्रोश और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुइथाकला भेज दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, डॉ. गोपेश कुमार सिंह पांच वर्षों से अधिक समय से नौपेड़वां CHC में तैनात थे, जो तबादला नीति का उल्लंघन था। उन पर आरोप है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहने को प्राथमिकता देते थे। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर क्षेत्र की जनता में लंबे समय से असंतोष था। बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने भी अस्पताल की बदहाली और अधीक्षक के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद विभाग में हलचल तेज हो गई थी। अस्पताल परिसर में स्थिति गंभीर थी। इस्तेमाल की गई मेडिकल सिरिंज, संक्रमित सुइयां, दवाओं के खाली डिब्बे और अन्य खतरनाक बायोमेडिकल कचरा खुले में फेंका जा रहा था। नियमों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण न होने के कारण यह कचरा हवा और जमीन के संपर्क में आकर बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा था। परिसर में आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता था, जिससे बच्चों और आम नागरिकों में संक्रमण फैलने का सीधा जोखिम था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, खुले में फेंकी गई संक्रमित सुइयों और सिरिंज से एचआईवी, हेपेटाइटिस–बी और सी जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। मौके पर कुत्ता काटने के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटी–रेबीज वैक्सीन की सुइयां भी खुले में लावारिस पड़ी मिलीं। यह स्थिति स्वास्थ्य प्रबंधन की घोर संवेदनहीनता और लापरवाही को दर्शाती है।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षोत्सव में देशभक्ति गीतों और लोकनृत्य की छटा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित दीक्षोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर देशभक्ति और लोकसंस्कृति के रंगों से सराबोर हो उठा। छात्राओं ने देशभक्ति गीतों एवं लोकनृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव तथा सह–संयोजक अनू त्यागी रहीं। कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगीत और लोककला केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक मूल्यों के सशक्त संवाहक हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ज्ञान के साथ–साथ संस्कार, सृजनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर देशभक्ति गीतों और लोकनृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं और पूरे परिसर में राष्ट्रभक्ति तथा उत्साह का वातावरण बना रहा। दीक्षोत्सव के अंतर्गत विश्वविद्यालय में "विकसित भारत /2047" विषय पर पोस्टर, काव्य लेखन एवं लोकनृत्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसके पूर्व विश्वविद्यालय परिसर में पुस्तक पठन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुलपति सभागार सहित सभी विभागों में शिक्षक एवं छात्र–छात्राओं ने अपनी पसंद की पुस्तक का सामूहिक अध्ययन किया तथा उस पर अपने विचार साझा किए। पुस्तक पठन कार्यक्रम के संयोजक डॉ. अनुराग मिश्र रहे। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

जौहर यूनिवर्सिटी और सोनम वांगचुक के समर्थन में सपा यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही कार्रवाई और लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के विरोध में प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारियों के हाथों में किताबें थीं, जिन पर एक खिलौना बुल्डोजर रखा गया था और उसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया।पुलिस द्वारा रोके जाने के विरोध में कई कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 से 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस बस के माध्यम से ईको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में प्रदर्शन स्थल को खाली करा दिया।प्रदर्शन में शामिल सपा नेता उदय सिंह ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो अन्य संस्थानों और कार्यालयों के निर्माण संबंधी मामलों की भी समान रूप से जांच होनी चाहिए।वहीं, प्रदर्शनकारी मनीष कुमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति नकारात्मक रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।

हज–2027 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 24 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ, (संवाददाता)। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने सर्कुलर–3 जारी कर हज–2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई, 2026 से बढ़ाकर 24 जुलाई, 2026 कर दी है। इच्छुक आवेदक अब निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।हज–2027 के इच्छुक आवेदकों से अपील की गई है कि वे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर शीघ्र ऑनलाइन आवेदन पूरा करें। जिन आवेदकों ने पंजीकरण तो करा लिया है, लेकिन किसी कारणवश आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, वे भी 24 जुलाई तक अपना आवेदन पूर्ण कर लें। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।हज कमेटी ने यह भी कहा है कि जिन आवेदकों को अभी तक भारतीय अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, वे तत्काल संबंधित पासपोर्ट कार्यालय से संपर्क कर पासपोर्ट प्राप्त करें, ताकि अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सके। हज यात्रियों के चयन के लिए 30 जुलाई, 2026 को मुंबई स्थित हज हाउस में ऑनलाइन कुर्रा (डिजिटल रैंडम चयन) किया जाएगा। चयनित हज यात्रियों की सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा चयन की सूचना एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी।चयनित सभी हज यात्रियों को 10 अगस्त, 2026 तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम धनराशि हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में जमा करनी होगी।

सहकारिता किसानों की समृद्धि का सबसे प्रभावी माध्यम – ए. के. शर्मा

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने सोमवार को जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मऊ की मधुबन शाखा के नवीन भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने नवीन भवन के निर्माण पर क्षेत्रवासियों, बैंक प्रबंधन और सहकारी समिति के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने सहकारी बैंकों और समितियों पर समय रहते ध्यान दिया होता तो ऐसे आधुनिक भवन वर्षों पहले बन चुके होते।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और ष्सहकारिता से समृद्धिष् का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि आज सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण, गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने किसानों से सामूहिकता और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यही भावना ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए।घोसी सहकारी चीनी मिल के संबंध में मंत्री ने कहा कि सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आगामी पेराई सत्र को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जेलों को आधुनिक और सुधारोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही सरकार – दारा सिंह चौहान

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार जेलों को आधुनिक, सुरक्षित और सुधारोन्मुख बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कारागारों का उद्देश्य केवल बंदियों को निरुद्ध रखना नहीं, बल्कि उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी है। इसके लिए जेलों में नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।कारागार मंत्री सोमवार को डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में आयोजित कारागार अधिकारी संवर्ग के 123वें तथा जेल वार्डर संवर्ग के 179वें सत्र के पासिंग आउट परेड एवं दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने परेड का निरीक्षण और सलामी लेकर की।

जौनपुर में एफएमडी टीकाकरण अभियान के आठवें चरण का शुभारंभ, छह लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने बुधवार को जौनपुर में खुरपका–मुंहपका (एफएमडी) रोग नियंत्रण टीकाकरण अभियान के आठवें चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद में यह अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर तक संचालित होगा, जिसके तहत लगभग छह लाख गोवंश एवं महिषवंशीय पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि पशुपालन किसानों और पशुपालकों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेश सरकार पशुधन को अमूल्य संपत्ति मानते हुए उसे संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि एफएमडी टीकाकरण अभियान का सातवां चरण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है और अब आठवें चरण के माध्यम से अधिकाधिक पशुओं को रोग से सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय पर टीकाकरण से खुरपका–मुंहपका जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी से बचाव संभव है। इससे पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा होगी, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की कि वे विभागीय टीम के सहयोग से अपने सभी पशुओं का निर्धारित समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि एफएमडी एक विषाणुजनित एवं अत्यंत संक्रामक रोग है, जो संक्रमित पशुओं से स्वस्थ पशुओं में तेजी से फैलता है। यह रोग विशेष रूप से गोवंश एवं महिषवंशीय पशुओं को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, चारा छोड़ देना, दूध उत्पादन में कमी, मुंह और खुर में छाले पड़ना तथा लंगड़ापन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस रोग की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय समय पर टीकाकरण है। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी पशुपालकों से अपील की कि वे इस निःशुल्क अभियान का लाभ उठाते हुए अपने पशुओं का अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराएं, ताकि पशुधन सुरक्षित रहे और दुग्ध उत्पादन के साथ उनकी आय में भी वृद्धि हो सके।

लखनऊ– लापता युवक के कथित अपहरण मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)।राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र में लापता युवक गुलफाम अहमद के कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस अब लापता युवक की तलाश तेज कर चुकी है, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।पुलिस के अनुसार, 2 जून 2026 को 22 वर्षीय गुलफाम अहमद के लापता होने पर चिनहट थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। मामले की जांच उपनिरीक्षक रितेश सिंह को सौंपी गई थी। इसके बाद 19 जुलाई को गुलफाम के भाई इस्तियाक अहमद, निवासी ग्राम ज्ञानीपुर, थाना शिवगढ़, जनपद सुल्तानपुर की तहरीर पर गुमशुदगी को अपहरण के मामले में परिवर्तित करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल युवक की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध के रूप में चिन्हित समीर (22), निवासी कंचनपुर मटियारी, थाना चिनहट, को डूडा कॉलोनी, हरदाशी खेड़ा क्षेत्र से हिरासत में लेकर पूछताछ की।पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सीएनजी पंप पर वाहन आगे बढ़ाने को लेकर गुलफाम अहमद से उसका विवाद हो गया था। आरोपी के कथन के अनुसार, विवाद के बाद उसने अपने साथियों आदिल, साहिल और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर गुलफाम को जबरन वाहन में बैठाया और उसके साथ मारपीट की। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मारपीट के बाद गुलफाम को बाराबंकी के देवा रोड के पास किसी स्थान पर सड़क किनारे छोड़ दिया गया। हालांकि उसने यह भी कहा कि इसके बाद गुलफाम कहां गया, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना में संलिप्तता पाए जाने पर समीर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार गुलफाम अहमद की तलाश में जुटी हैं और घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है।

आवेदन से वंचित दंपती शिक्षकों को मिला दो सप्ताह का समय

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से सोमवार को परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2026–27 के मामले में आवेदन से वंचित दंपती शिक्षकों, दिव्यांग एवं अन्य पात्र शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इन्हें आवेदन के लिए दो सप्ताह का और समय दिया है। कोर्ट को बताया गया कि 20 जून के बाद जारी स्पष्टीकरण एवं पीटीआर के कारण कई शिक्षक आवेदन नहीं कर सके थे, जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह आदेश ज्योति कुशवाहा एवं चार अन्य शिक्षकों की याचिका पर दिया। इसमें शिक्षक दंपती समेत अन्य पात्र शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने 22 जून के सर्कुलर से प्रभावित शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन देने का समय सोमवार से दो सप्ताह बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि अगर, याचीगण या उनके समान अन्य शिक्षक इसके लिए दो सप्ताह में आवेदन करें तो उनके मामले को कानून के अनुसार गौर करके निस्तारित किया जाएगा। कोर्ट ने इसके लिए बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों को अखबारोंध्वेबसाइट पर प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन निर्देशों के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जौनपुर में कांग्रेस का सत्याग्रह, कई नेता रहे नजरबंद

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन कर धरना–प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव सत्यवीर सिंह ने कहा कि अपने अधिकारों और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज करना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉ. राकेश मिश्र श्मंगला गुरुश तथा जिला उपाध्यक्ष लाल प्रकाश पाल ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की। धरना–प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर, राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध को देखते हुए जिले में पुलिस और प्रशासन सतर्क रहा। जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह को सुजानगंज स्थित उनके आवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ नजरबंद रखा गया। वहीं शहर अध्यक्ष आरिफ खान, सभासद शहनवाज मंजूर, संगठन प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, कांग्रेस नेता रामसिंह बांकुरे, ओमकार यादव तथा मछलीशहर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद सैफ को भी पुलिस ने उनके आवास से बाहर नहीं निकलने दिया। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए विरोध दर्ज कराया।

दवा व्यापारियों ने माना– चल रहा नकली दवा का धंधा

लखनऊ, (संवाददाता)। अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में नकली दवाओं का धंधा चल रहा है। कई जिलों में यहां से नकली दवा की आपूर्ति हो रही है। धंधेबाजों ने नकली दवाओं की सप्लाई चेन बना रखी है। एफएसडीए इस नेटवर्क तोड़ने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। वह शिकायत के बाद ही छापेमारी करती है। लखनऊ केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रवक्ता मयंक रस्तोगी ने कहा कि बाजार में नकली दवाओं की मौजूदगी अब गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। असली जैसी पैकिंग और बैच नंबर होने के कारण नकली दवाओं की पहचान करना मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नकली दवा बनाने और सप्लाई करने वाले गिरोहों पर नकेल कसी जाए। नकली दवा कारोबारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो। एफएसडीए के सहायक मंडलायुक्त बृजेश यादव ने बताया कि लखनऊ से गोंडा, सीतापुर, अयोध्या, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में नकली दवाओं की आपूर्ति होने के सुराग मिले हैं। संगठित नेटवर्क कूरियर व निजी वाहनों से दवाओं की खेप भेजता है। असली दवाओं के बीच नकली दवाएं मिलने से परिवहन के दौरान शक की आशंका कम रहती है। एफएसडीए अब इन जिलों में भी दवा आपूर्ति की निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

केजीएमयू की कैंटीन में कॉकरोच मिलने पर शासन सख्त

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू के शताब्दी भवन स्थित कैंटीन के फ्रीजर में केक पर कॉकरोच रेंगने के मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने केजीएमयू प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तलब की है। घटना 27 जून की है। इसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद अपर मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए हैं। शासन ने रिपोर्ट में कैंटीन की सफाई व्यवस्था की जानकारी मांगी है। खाद्य सामग्री के भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण और मरीजों व तीमारदारों को परोसे जाने वाले भोजन के मानकों की भी जानकारी मांगी है। शासन ने ट्रॉमा सेंटर में निर्माण कार्य के चलते एंबुलेंस के फंसने और मरीजों को हो रही परेशानी का भी संज्ञान लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने केजीएमयू प्रशासन से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ट्रॉमा सेंटर पहुंचने वाली एंबुलेंस और गंभीर मरीजों के आवागमन में कोई बाधा न आए। शासन ने निर्माण एजेंसी और अस्पताल प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। शासन की सख्ती के बाद केजीएमयू प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने की कवायद शुरू कर दी है।

प्रशिक्षण पूरा कर जेल अधिकारियों ने दी सलामी

लखनऊ, (संवाददाता)। आलमबाग स्थित डॉ. संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान (जेल ट्रेनिंग स्कूल) में सोमवार को कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्रशिक्षण पूरा कर चुके जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। प्रशिक्षण में सर्वोच्च प्रशिक्षणार्थी का अवॉर्ड अधिकारी संवर्ग में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जेल अधीक्षक टामन और जेल वार्डर संवर्ग में बागपत में तैनात जेल वार्डर अतुल यादव को दिया गया।

आरपीएफ कर्मियों ने लोगो को किया जागरूक

अयोध्या ।आरपीएफ अयोध्या कैंट द्वारा रेलवे ट्रैक के आसपास रह रहे लोगों को आये दिन जागरूक किया जा रहा है ।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही ने बताया कि इसी अभियान के तहत मंगलवार को रेलवे नियमों का पालन व रेल से संबंधित अपराधों पर आम जनता व यात्रियों को जागरूक किया गया ।यह अभियान अयोध्या कैंट से फतेहगंज, हैदरगंज, बेनीगंज क्षेत्र व अयोध्या धाम तक चला ।इस मौके पर आरपीएफ कर्मियों ने लोगों को रेलवे ट्रैक पार ना करने,रेलगाड़ी पर पत्थर ना मारने, रेलवे क्रासिंग गेट को सावधानीपूर्वक पार करने, ज्वलनशील पदार्थ लेकर रेलगाड़ी में यात्रा ना करने व रेलवे परिसर मे लेकर ना आने, अनावश्यक रूप से चौन पुलिंग न करने, रेलवे परिसर, रेलवे ट्रैक के किनारे, कूड़ा कचरा ना डालने, मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने की अपील किया।

महिला उप निरीक्षक चेतना पाण्डेय ने गोशाईगंज बाजार मे महिलाओ को किया जागरूक

अयोध्या ।मिशन शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी,सीओ सदर प्रतीक कुमार के निर्देश पर महिला उप निरीक्षक चेतना पांडेय ने गोशाईगंज थाना क्षेत्र मे बाजार मे महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरुक किया ।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद महिलाओं तथा बालिकाओं को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई ।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया ।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया ।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया ।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला उप निरीक्षक प्रिया ने मिशन शक्ति अभियान के तहत किया जागरूक

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। घर से बाहर निकलते समय महिलाये व बालिकाये विशेष सावधानी बरतें ।बाहर निकलते समय आसपास की गतिविधियों पर अवश्य ध्यान दे और देखे कि किसी अजनबी व संदिग्ध व्यक्तियों की आप पर नजर तो नहीं है ।यह बातें शनिवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला उप निरीक्षक प्रिया ने पीआरडी कंचन व अन्य महिला पुलिस कर्मियों के साथ गुलाबबाड़ी,रीडगंज व अन्य चौराहों पर अभियान चलाते समय महिलाओ व बालिकाओं से कहीं ।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद महिलाओ व बालिकाओं से अपील किया कि आप सभी अपने आसपास दिखाई देने वाले संदिग्ध वस्तुओं व व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दें। किसी भी तरह की असम का देखते हुए इसकी सूचना महिला पुलिस व स्थानीय पुलिस को दे ।उन्होंने कहा कि जिससे समय रहते किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके ।इसके अलावा उन्होंने अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर मिशन शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक किया ।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षात्मक उपाय बताया ।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स जानकारी दिया ।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया ।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया ।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें ।कहा जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

2027 से पहले भाजपा का फोकस, उपसभापति पद पर दलित चेहरे पर भाजपा लगा सकती है दांव

गोरखपुर, (संवाददाता)। नगर निगम में उपसभापति का चुनाव जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सामाजिक संतुलन की रणनीति के तहत इस बार दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। संख्या बल के अभाव में समाजवादी पार्टी पहले ही मुकाबले से बाहर मानी जा रही है। नगर निगम अधिनियम के अनुसार, उपसभापति का चुनाव पांच अगस्त तक होना है लेकिन इसकी प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह में पूरी कराए जाने की तैयारी है। चुनाव की आहट के साथ ही निगम सदन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि पिछले 36 वर्षों में इस पद के लिए 19 चुनाव हो चुके हैं लेकिन अब तक किसी दलित पार्षद को उपसभापति बनने का अवसर नहीं मिला। हाल ही में हुए नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव में भाजपा ने पुराने चेहरों के बजाए नए पार्षदों को मौका देते हुए दो पिछड़ा, दो दलित और एक सामान्य वर्ग के सदस्य को शामिल कर सामाजिक संतुलन का संदेश दिया था। अब माना जा रहा है कि यही रणनीति उपसभापति चुनाव में भी दोहराई जा सकती है। पद के लिए दो महिला पार्षद भी दावेदारी कर रही हैं, जिनमें एक पिछड़ा वर्ग और दूसरी सामान्य वर्ग से हैं। वहीं, दलित वर्ग के एक वरिष्ठ पार्षद भी मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। वह तीन बार पार्षद रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी भी एक कार्यकाल तक पार्षद रह चुकी हैं। हालांकि उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला भाजपा संगठन और शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही होगा।

गीडा में 24 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। गीडा प्रबंधन ने 24 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन कर दिया है। इन इकाइयों में रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक उत्पाद समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी यूनिट्स स्थापित होंगी। इससे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। गीडा प्रशासन ने 510 वर्गमीटर से लेकर 4800 वर्गमीटर तक के कुल 24 औद्योगिक भूखंड विभिन्न सेक्टरों में आवंटित किए हैं। सेक्टर–26 में 510 वर्गमीटर के दो, सेक्टर–13 में 1950 वर्गमीटर के तीन, 2100 वर्गमीटर के सात और 3250 वर्गमीटर का एक भूखंड आवंटित किया गया है।

खुरपका मुँहपका टीकाकरण अभियान के आठवें चरण का हुआ शुभारम्भ’

रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’

‘हरदोई’ जिलाधिकारी अनुनय झा ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका मुँहपका टीकाकरण अभियान के आठवें चरण का हरी झण्डी दिखाकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर टीकाकरण करने हेतु गठित टीमों को रोस्टर अनुसार ग्रामों में पहुँचकर टीकाकरण पशुपालक के द्वार पर जाकर निःशुल्क करने हेतु रवाना किया गया। ख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त पशुपालकों से अपील की गयी कि टीम द्वारा किये गये टीकाकरण का विवरण भारत पशुधन ऐप पर कान के छल्ला नम्बर के साथ अपलोड किया जायेगा, इस हेतु टीकाकरण कार्यकर्ता को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। घ्इसी क्रम में विकास खण्ड मल्लावां में माननीय विधायक आशीष सिंह आशू जी, विकास खण्ड माधौगंज में मा. विधायक जी की पूज्यनीय माता जी विमला देवी जी के कर कमलों से तथा इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न ब्लाकों में माननीय प्रमुख एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों द्वारा हरी झण्डी दिखाकर उक्त अभियान का शुभारम्भ किया गया। उक्त अभियान जनपद में दिनांक 22.07.2026 से 08.09.2026 तक (कुल 45 दिवस) संचालित होगा। अभियान के अन्तर्गत गठित टीमों द्वारा जनपद में 8,38,000 (गोवंशीय एवं महिषवंशीय) पशुओं में खुरपका मुँहपका रोग की रोकथाम हेतु टीकाकरण पशुपालक के द्वार पर जाकर निःशुल्क किया जायेगा। टीकाकरण के दौरान 08 माह से अधिक गाभिन पशु एवं 04 माह से छोटे बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ध पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं पशुमित्र उपस्थित रहे।

मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की बैठक सम्पन्न

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। मंडलायुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की सप्तम बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गयी ।इस बैठक में पर्यटकों के सुविधार्थ हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी जयेन्द्र कुमार के द्वारा विगत वर्ष 2024–25 की 17 परियोजनाओं के अद्यतन प्रगति रिपोर्ट एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा स्वीकृति 17 परियोजनाओं की प्रगति व हस्तान्तरण किये जाने वाली परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई ।बैठक में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर, उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अनुराज जैन सहित सम्बंधित अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद द्वारा विगत वर्ष 2024–25 में स्वीकृत कुल 17 परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट समिति के समक्ष रखी गयी ।आयुक्तध्अध्यक्ष द्वारा प्रचलित कार्यों में प्रगति करने तथा निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। शेष परियोजनाओं को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रस्तावित कार्ययोजना का भी प्रस्तुतीकरण, श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से किया गया।

दिव्यांग छात्रा ट्राई साइकिल अनुदान के लिए करे आवेदन - शशांक त्रिपाठी

अयोध्या। डीएम शशांक त्रिपाठी ने जनपद के सभी दिव्यांगजनों के हित मे संचालित समस्त संस्थाओं को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग–2 द्वारा स्कूल जाने वालीध् शिक्षण–प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई–ट्राईसाइकिल प्रदान किये जाने हेतु अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।बताया कि ई–ट्राईसाइकिल हेतु इच्छुक सभी दिव्यांग छात्राएं विभागीय वेबसाइट ीजजचेरूध्धूक.नचु.पद पर ऑनलाइन कराया जाना सुनिश्चित करें ।ई–ट्राईसाइकिल हेतु पात्रता की शर्तों का पालन करना होगा ।बताया कि आवेदक दिव्यांग छात्रा की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो तथा उत्तर प्रदेश का निवासिनी हो ।दिव्यांग छात्रा या उसका परिवार आयकर दाता न हो, किन्तु शर्त यह है कि सर्वप्रथम लक्ष्य के सापेक्ष गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को संतृप्त किया जाएगा ।यदि उसके पश्चात लक्ष्य अवशेष रहता है तो दिव्यांगता घटते हुए कम में तथा आय के बढ़ते हुए कम में लाभान्वित किया जाएगा ।दिव्यांग छात्रा का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा स्वस्थ्य हो, ई–ट्राईसाकिल पर बैठ कर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हो। यदि किसी छात्रा को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उक्त उपर्युक्त प्रपत्रों के साथ किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विकास भवन कमरा नं0–06 में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा किसी भी समस्या के समाधान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक अरविन्द कुमार के मो.नं.–7376403087 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आप ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा

प्रयागराज, (संवाददाता)। आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने सोमवार को प्रयागराज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक के समर्थन में किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की। उनका कहना था कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी के काशी प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को भी उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और जब छात्र अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं तो उनके साथ सख्ती बरती जाती है। तिवारी ने शिक्षाविद सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया, जो शिक्षा सुधार की मांग को लेकर कई दिनों तक आमरण अनशन पर थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उन्हें जबरन अनशन स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। आप नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।

श्रीराम मन्दिर से रामधन गबन और लूट विवाद के बीच मंदिर ट्रस्ट की आज चल रही अहम बैठक

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार श्रीवास्तव

अयोध्या। श्री राम जी मन्दिर से रामधन गबन और लूट विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक चल रही है ।अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक आयोजित की गई ।इस बैठक में नए महासचिव की नियुक्ति, तीन खाली ट्रस्टी पदों को भरने, सीईओ चयन प्रक्रिया, दान की गिनती और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने सहित एस आईटी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है ।अंतिम फैसलों का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है

सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर टीम को किया रवाना

अयोध्या ।जनपद में 22 जुलाई से 8 सितंबर तक 45 दिनों तक चलने वाले खुरपका,मुंहपका टीकाकरण अभियान की शुरुआत सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने किया ।इस मौके पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया ।इस मौके पर सीवीओ डॉक्टर इंद्रदेव ने बताया कि पशुधन

को खुरपका–मुंहपका जैसी संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए 22 जुलाई से 08 सितम्बर तक 45 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ।बताया कि अभियान के दौरान जिले के 136691 गोवंशीय और 302358 महिष वंशीय पशुओं को निःशुल्क टीके लगाने के लिए चिन्हित किया गया है ।इसके लिए 29 टीमें गठित की गई हैं,जो रोस्टर के अनुसार गांव–गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी ।इस मौके पर उन्होंने सीवीओ डॉ इंद्रदेव के अलावा उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अरुणेंद्र, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ शशि,डॉ कमलेश यादव, डॉ रवींद्र , डॉ नीरज गुप्ता व मोबाइल वेटरनरी यूनिट के डॉक्टर मौजूद रहे।

कैंट रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था के चलते रेल यात्री परेशान

अयोध्या ।अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर इस समय अव्यवस्था का बोलबाला है ।जिसके चलते रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।इस समय सभी प्लेटफार्मो पर बारिश के चलते पानी भरा रहता है। वहीं प्लेटफार्म नंबर एक से दो तीन पर जाने के लिए सबवे में हल्की बारिश के चलते पानी भरा रहता है ।वही प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 तथा 3 पर जाने के लिए स्वाचलित सीढी भी बंद रहती है ।सबवे में पानी भरे रहने तथा स्वचालित सीढ़ी बंद होने के चलते इन प्लेटफार्म को जाने के लिए पुल का सहारा लेना पड़ता है। बताते चले कि प्लेटफार्म नंबर दो तथा तीन से होकर गुजरने वाली ट्रेन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को खासकर बुजुगों, दिव्यांगों, मरीजों को स्वचालित सीढ़ी ना व सबवे मे पानी भरे रहने के चलते पुल का सहारा लेना पड़ता है। जिसके चलते इन रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित रेल अधिकारियो तथा कर्मियों का ध्यान नहीं जा रहा है।

शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अवैध रूप से संचालित हो रहे सैकड़ो कोचिंग तथा लाइब्रेरी

अयोध्या ।शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कुकुरमुत्ते की तरह लाइब्रेरी कोचिंग संस्थान अवैध रूप से संचालित हैं ।देखा जाए तो अवैध रूप से संचालित लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थान ना तो अग्नि शमन विभाग के मानक पर खड़े उतर रहे हैं,और ना ही शिक्षा विभाग पर ।ठीक इसके विपरीत इन अवैध कोचिंग संस्थान तथा लाइब्रेरी के संचार को द्वारा भोले भाले तथा गरीब तपके के छात्रों तथा उनके अभिभावकों से शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं ।परंतु यहां पर अध्यनरत छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के नाम पर इन संस्थानों पर ना तो अग्निशमन के यंत्र उपलब्ध हैं और ना ही अग्निशमन मानक के अनुसार निर्माण ही है ।जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के मुताबिक पंजीकृत लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थान महज तीन दर्जन तक ही हैं ।जबकि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक सैकड़ो की संख्या में अवैध रूप से लाइब्रेरी तथा कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं ।बीच–बीच में जब कभी अग्निकांड या फिर अन्य कोई प्राकृतिक आपदा कही इन कोचिंग संस्थानों तथा लाइब्रेरी पर होती है तब खानापूर्ति के लिए अयोध्या जनपद में भी कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी स्कूल कॉलेज जो कि अवैध रूप से संचालित हैं उनके ऊपर शिक्षा विभाग के अधिकारी एक–दो दिन कार्यवाही करते हैं उसके बाद फिर मामला ठंडा बस्ती में चला जाता है ।इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया शीघ्र ही जिले में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों लाइब्रेरी स्कूल कॉलेज पर कार्यवाही की जाएगी।

सम्मेलनों में व्यस्त जनप्रतिनिधि, बदहाल सड़कें और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जनपद में एक ओर जनप्रतिनिधि लगातार सम्मेलनों,बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में व्यस्त नजर आ रहे हैं,वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जमीनी हकीकत विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। क्षेत्र की मुख्य एवं संपर्क मार्गों की हालत लगातार खराब होती जा रही है ।सड़कों पर बने बड़े–बड़े गड्ढे आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।इसके साथ ही कई क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति से आम जनजीवन प्रभावित है। पर्यावरण संरक्षण के दावों के बीच अवैध रूप से हरे–भरे पेड़ों की कटाई भी जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित विभागों और प्रशासन की अनदेखी के कारण यह अवैध कारोबार बेखौफ संचालित हो रहा है। वहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के बजाय सम्मेलनों और औपचारिक कार्यक्रमों में अधिक व्यस्त दिखाई देते हैं। लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सड़क, बिजली, पर्यावरण संरक्षण तथा भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।